(b) Pass-books have been issued in some States like Andhra Pradesh, Gujarat Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Sikkim and Tamil Nadu.

(c) A Conference of Revenue Ministers was held on the 14th March, 1992. In this Conference it was recommended that all States should take legal and administrative action within a time frame of 3 to 6 months to ensure that land holders are given Patta Pass-books. The State Governments have been advised accordingly.

विकास परियोजनाओं में ग्रामीण लोगों का योगदान

1316. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ग्रामीण विकास परिषद के माध्यम से निष्पादित की जा रही विकास परियोजनाओं में ग्रामीण लोगों का कितने प्रतिशत योगदान है ;

(ख) ग्रामीण लोगों को अनुसन्धान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या-क्या विभिन्न योजनाएं हैं; ग्रामीण लोगों द्वारा अब तक कितने पेटेंटों अथवा प्रतिलिप्यधिकारों का दावा किया है और उनका वार्षिक औसत कितना है ;

(ग) ग्रामीण लोगों द्वारा और अधिक अनुसन्धान करवाने और उनके लिए और अधिक प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करवाने की समयबद्ध योजना क्या है ; और

(घ) सभी ग्रामीण विकास पत्रिकाओं के नामों को हिन्दी में बदलने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि इस समय इन सभी पत्रिकाओं के नाम अंग्रेजी में हैं और बहुत अटपटे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) सरकार को ग्रामीण विकास परिषद तथा उसके माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विकास परियोजनाओं की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (घ) ग्रामीण लोगों द्वारा अनुसंधान किए जाने के बारे में कोई योजना नहीं है । तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों अर्थात राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना, आपरेशन रिसर्च, ऑनफार्म रिसर्च तथा "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम (लैब टू लैंड प्रोग्राम) की मार्फत अनुसंधान प्रौद्योगिकी के परिणाम को किसानों तक पहुंचाया जाता है; ग्रामीण लोगों द्वारा पेटेंटों अथवा प्रतिलिप्याधिकारों का दावा किए जाने के बारे में कोई विशेष योजना नहीं है ।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय दो मासिक प्रकाशन–कुरुक्षेत्र और ग्रामीण विकास न्यूजलेटर प्रकाशित करता है । ग्रामीण जनसंख्या के काफी बड़े वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के उददेश्य से ये दोनों प्रकाशन हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं । ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों के नामों को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Villages not covered by Drinking Water Mission

1317. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Drinking Water Mission has issued a Statement that only 4,346 villages are left to be covered by their mission ;

(b) how many villages were actually covered by the Drinking Water Mission; and

(c) what are the details of amount spent by the mission so far, giving yearly figures ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) 3326 'No Source' problem villages remained to be provided safe drinking water facilities as on 1-4-92.

(b) During the period from 1991-92, 1,58,396 'No Source' problem villages were covered with safe drinking water facilities under the State sector Minimum Needs Programme (MNP) and National Drinking Water Mission/Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP).

(c) The details of the amount spent by the States and the Technology Mission (TM) during the above period are given below :—

(Rs. in crores)

Sl. No.	Year	MNP	TM/ARWSP
1	1986-87	470.37	321.37
2	1987-88	505.89	386.39
3	1988-89	537.62	437.86
4	1989-90	552.41	462.52
5	1990-91	572.28	410.54
6	1991-92	443.69*	644.41

*Provisional upto January, 1992.

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दिए गए ऋण

1318. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 और 1991 के वर्षों के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और बीससूत्री कार्यक्रमके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बैंकों द्वारा कितनी राशि के ऋण दिये गये ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना से जिला-वार कितने-कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अंतर्गत बैंकों द्वारा 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के वर्षों के दौरान दिया गया ऋण क्रमश: 28849.89 लाख रुपये, 31133.33 लाख रुपये तथा 29830.32 लाख रुपये (अनंतिम) था । जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में सूचना का संबंध है, यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) यह मंत्रालय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिलावार लाभान्वित हुए लोगों की संख्या के बारे में निगरानी नहीं करता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के वर्षों के दौरान क्रमश: 6.30 लाख, 5.09 लाख और 4.62 लाख (अनंतिम) परिवार लाभान्वित हुए थे ।

Physical Target for Assistance to Families below the Poverty Line under IRDP

1319. SHRI DHULESHWAR MEENA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Central Government has drastically pruned the physical target for providing assistance to families below the poverty line under the Integrated Rural Development Programme;

(b) the physical target for 1991-92 and the number of families provided assistance and the estimated capital outlay involved;

(c) whether Government have further delinked the financial provisions of the Training for Rural Self Employment (TRYSEM) Scheme from IRDP;